भारतवंशी भार्गव बदलेंगे तस्वीर

हाल के दिनों में दुनिया भर में अरबपति उद्योगपतियों में सामाजिक सरोकारों के लिए अपनी संपत्ति दान करने का सिलसिला तेज हुआ है। इस क्रम में अमेरिका के जाने-माने भारतवंशी खरबपति मनोज भार्गव भी हैं, जिन्होंने वारेन बाफेट और बिल गेट्स के साथ मंच से अपनी आय का 90 फीसदी हिस्सा दान करने का ऐलान किया था। दान की गई अरबों की संपत्ति भार्गव अपने वतन के वंचितों के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गैर सरकारी संगठन हंस फाउंडेशन को यह जिम्मा सौंप रखा है। फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रवासी भारतीय ***श्वेता रावत*** *से* ***संजय मिश्रा*** *ने बात की-*

सप्ताह का इंटरव्यू

● *गैर सरकारी संगठनों के कामकाज पर हाल के वर्षों में सवाल उठे हैं, ऐसे में नई सरकार के दौर में आपके जैसे एनजीओ के लिए काम करने का कितना मौका है?*

कुछ एनजीओ की वजह से बाकी को भी शक की निगाह से देखा जाता है। मगर हंस फाउंडेशन की खास बात यह है कि हम तो किसी से फंड लेते ही नहीं। मनोज भार्गव की दान की गई आय से ही हम पिछले पांच वर्षों से उत्तराखंड और भारत के तमाम पिछड़े जिलों में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एनजीओ के लिए काम आसान किया है, क्योंकि उन्होंने अपने एजेंडे में जो मुद्दे रखे हैं यानी स्वच्छ भारत, युवा पेशेवरों के लिए हब बनाना और स्किल डेवलपमेंट- इन सब क्षेत्रों में हम भी आगे बढ़ रहे हैं।

● *भार्गव के इरादों के अनुरूप अब तक आपने वंचित इलाकों का चेहरा बदलने के लिए क्या किया है?*

बुनियादी स्वास्थ्य क्षेत्र में देश के ग्रामीण इलाकों की स्थिति बेहद दयनीय है। इसलिए हमने उत्तराखंड से अस्पताल योजना की शुरुआत की है। एक अस्पताल सतपुली कोडवाल के पास है और दूसरा हरिद्वार में आई केयर अस्पताल शुरू किया गया है, जो कम कीमत पर गरीबों की आंखों की सर्जरी और अन्य इलाज कर रहा है। इसके अलावा 17 राज्यों में मोबाइल मेडिकल केयर प्रोजेक्ट काफी सफलता पूर्वक चल रहा है। हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी इसे चलाया है।

● *गांवों और पिछड़े इलाकों पर फोकस की आपने बात की, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर भी आपकी कुछ योजना है?*

हम सरकार की बराबरी तो नहीं कर सकते, मगर फाउंडेशन ने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री की परिकल्पना की तर्ज पर ही आदर्श राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है, क्योंकि यह एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी बहुत है। तस्वीर बदलनी है, तो सबसे पहले हमें गांव और गरीबों के हालात बदलने होंगे। सांसदों को ही नहीं एनजीओ, बड़े अरबपतियों और हर सक्षम व्यक्ति को भारत के गांवों का चेहरा बदलने के लिए तत्काल आगे आने की जरूरत है।

● *सांसद ही एक-दो गांव गोद लेने में मशक्कत कर रहे हैं, फिर आर्थिक रूप से राज्य को गोद लेने सरीखे कार्य करने में आर्थिक रूप से संगठन कितना सक्षम है?*

हम एनजीओ हैं, जहां लालफीताशाही नहीं है। उत्तराखंड को गोद लेने से एक साल में बदलाव नहीं आएगा। हमारी योजना शुरुआत में गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ गांवों में काम शुरू करने की है। भार्गव अपनी दान की आय की पूरी रकम वंचित लोगों की भलाई के लिए ही दे रहे हैं। हंस फाउंडेशन ने पांच साल में करोड़ों खर्च किए हैं और अगले एक साल में हमारी 300 करोड़ रुपए तक की कार्ययोजना है।

● *उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने का ब्लूप्रिंट क्या है?*

यहां के गांवों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां लोग रहना नहीं चाहते। विद्यालय नहीं होने के कारण लोग बच्चों को लेकर शहर में आ जाते हैं। नौकरी नहीं होने के कारण बाहर चले जाते हैं। गांव में केवल वृद्धजन हैं, जो बच्चों या एनजीओ की पेंशन के माध्यम से जी रहे हैं। हमारी सोच यह है कि हम उन गांवों में लोगों को अच्छे विद्यालय और अस्पतालों की सुविधा दें, ताकि लोग बाहर जाने को मजबूर न हों। इस योजना का विस्तृत खुलासा आगामी चार नवंबर को खुद मनोज भार्गव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दिल्ली में एक बड़े चैरिटी कार्यक्रम में करेंगे।

> हंस फाउंडेशन किसी से फंड लेता ही नहीं। हम पांच वर्षों से उत्तराखंड और देश के *तमाम पिछड़े* जिलों में सामाजिक कार्य कर रहे हैं।

● *आप खुद अमेरिका में रहने वाली एक युवा प्रवासी भारतीय हैं, फिर कैसे इन योजनाओं को अंजाम देंगी?*

प्रवासी होते हुए भी मैं काफी समय फाउंडेशन के काम के लिए भारत में बिताती हूं। बचपन से सामाजिक कार्य में परिवार की प्रतिबद्धता देखती आ रही हूं, इसलिए मनोज भार्गव ने जब अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लोगों के कल्याण में लगाने का फैसला किया, तो पारिवारिक रूप से जुड़े होने के कारण हमने इसे मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लिया।